

## वार्षिक ऋण योजना में राजस्थान के कृषि उत्पादन में कृषि ऋणों का प्रभाव

श्रवण कुमार

शोध छात्र

अर्थशास्त्र विभाग,

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, भारत

Email : [mlguddul@gmail.com](mailto:mlguddul@gmail.com)

---

### सारांश

ग्रामीण वित्त भारत की तरह एक विकासशील अर्थव्यवस्था में वित्त चिन्ता का विषय है यहाँ 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और ऋण महत्वपूर्ण गैर भूमि आदानों में से एक के रूप में माना जाता है। कृषि विकास की वृद्धि में वित्त का योगदान दो दृष्टिकोण अर्थात् आयाम ऋण की मात्रा और कृषि ऋण वितरण है। राष्ट्रीय कृषि नीति में न सिर्फ कृषि में 4 प्रतिशत वृद्धि प्रति वर्ष है बल्कि इसका वितरण भी समान है। कृषि क्षेत्रों और किसानों के विभिन्न वर्गों में उसी समय विश्व व्यापार के महत्वपूर्ण प्रावधानों में कृषि समझौतों के अन्तर्गत भारत का हिस्सा बढ़ाने की क्षमता है। जो उच्चतर ऋण माँग और उसके विकास में गति प्रदान करते हैं। 1935 में प्रभावी भारतीय केन्द्रीय बैंक कृषि एवं कृषि सम्बन्धित मामलों में रुचि लेने वाला शायद दुनियाँ का पहला बैंक है।

---

### प्रस्तावना

राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ जनसंख्या का 65 प्रतिशत हिस्सा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है और क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ बड़ी संख्या में किसानों के पास छोटे-छोटे खेत हैं, कम उत्पादकता के साथ कृषि से उत्पादन लगभग अपने परिवार के जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि देश के अधिकांश हिस्से पर अनुपयुक्त भूमि ने कब्जा कर लिया है जो लगभग 34.27 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है वर्ष 2013-14 में केवल 48.29 प्रतिशत क्षेत्र ही शुद्ध कृषित क्षेत्र था, और यह सकल फसली क्षेत्र का 61.45 प्रतिशत था इस कमी का कारण राज्य में सिंचाई पानी का अभाव व कृषि का प्रकृति पर निर्भर होना है क्योंकि राज्य का अधिकांश हिस्सा सुखा प्रभावित रहता है। यहाँ औसतन वर्षा 530 मिमी है जो अप्रत्याशित है। नतीजन राज्य में अक्सर सुखा पड़ना, आत्महत्याएँ जैसी घटनाएँ घटित होती हैं और लोगों की जान बचाने के लिए बड़ी मात्रा में धन खर्च करना पड़ता है। और पशुपालन व कृषि उत्पादन में प्रगति पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है, पशुओं के पालन-पोषण करने

व कृषि उत्पादन के किसानों को अधिक से अधिक धन उधार लेना पड़ता है और यह ऋण इस प्रकार का होना चाहिए जो किसानों को पर्याप्त मात्रा में और उपयुक्त ब्याज पर उपलब्ध होना चाहिए ताकि वे उत्पादन बढ़ा सकें और उर्वरक, बीज, बेहतर सिंचाई सुविधाओं आदि जैसे बेहतर कृषि आदानों का उपयोग कर सकें।

### अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के कृषि उत्पादन में उत्पादन ऋण का प्रभाव का अध्ययन करना है जो वर्तमान में कृषि एवं ग्रामीण विकास में अहम भूमिका अदा करता है। सक्षिप्त में प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं:-

- (1) कृषि ऋणों का राजस्थान में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु किये गये कार्यों की समीक्षा करना।
- (2) कृषि ऋणों का कृषि उत्पादन वृद्धि में योगदान का अध्ययन करना।

### परिकल्पना

- (1) कृषि ऋणों का कृषि उत्पादन में वृद्धि में धनात्मक योगदान है।
- (2) ऋण प्रदान करने वाली संस्थागत स्रोतों और किसानों के मध्य सहसम्बन्ध है।

### अध्ययन के स्रोत

वर्तमान अध्ययन के समुचित व कुशलतापूर्वक विश्लेषण के लिए निम्न स्रोतों से सम्बन्धित संमकों व विकास प्रारूप का उपयोग किया जायेगा।

- (1) राजस्थान सरकार द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स व विभिन्न सर्वेक्षण।
- (2) आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स।
- (3) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न वार्षिक दस्तावेज।

### शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन राजस्थान में कृषि ऋणों का कृषि उत्पादन में योगदान का अध्ययन क्षेत्र विषययुक्त जिसमें किसी विशिष्ट विधि के प्रयोग द्वारा लक्षित परिणाम प्राप्त करना संभव नहीं है। अतः इस हेतु आवश्यकतानुसार प्रमाप विचलन, सहसम्बन्ध गुणांक, कार्इवर्ग परिक्षण, सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य व्यक्तिगत रूप से वित्तीय संस्थाओं के प्रधान कार्यालय जाकर सूचनाओं व आँकड़ों के संग्रहण का रहा।

### कृषि ऋण के स्रोत

भारत में कृषि ऋण में दो मुख्य स्रोत हैं:-

#### (अ) गैर-संस्थागत स्रोत (पारम्परिक स्रोत)

कृषि को ऋण का एकमात्र आपूर्तिकर्ता पारम्परिक स्रोत कृषि एवं पेशेवर साहुकार, जमीदार, रिश्तेदार और मित्र, व्यापारी और कमीशन एजेन्ट आदि।

## (ब) संस्थागत स्रोत

यह कृषि ऋण के लिए संस्थागत व्यवस्था है संस्थागत स्रोत का मूल उद्देश्य किसानों को उनकी उत्पादकता बहाने और अपनी आय में अधिकतम करने में मदद करना है यह संस्थान अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण कम ब्याज पर उपलब्ध करवाते हैं साथ ही आवश्यकता के अनुसार यह ऋण संस्थान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करते हैं, जिनमें कॉर्पोरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक, वाणिज्यिक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और सरकार आदि को श्रेय जाता है साथ कृषि कार्यों में मार्गदर्शन जैसे कि बीज, उर्वरक और कीटनाशकों आदि का उपयोग, फसल उत्पादन बढ़ाने और अपने आप को अधिकतम करने के लिए, संस्थागत ऋण सहकारी समितियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। सरकार द्वारा वाणिज्यिक बैंक व भारतीय रिजर्व बैंक को कृषि और सम्बन्ध गतिविधियों के लिए फसल और निवेश ऋण दोनों पर अनुदान प्रदान करती है। कृषि ऋण के सम्बन्ध में नाबार्ड शीर्ष संस्थान है जो कृषि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अन्य वित्तीय एजेंसियों को पूर्णवित्त सुविधा प्रदान करता है भारतीय रिजर्व बैंक कृषि और उद्योगों के लिए नाबार्ड और आई.डी.बी.आई को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, और इन सबके लिए भारत में मौद्रिक नीति तैयार की जाती है।

### राजस्थान में बैंक की शाखाएँ

राजस्थान में कृषि क्षेत्र में वित्त प्रदान करने वाली बैंक शाखाओं की वर्ष 2014-15 में कुल 6804 थी। जिनमें वाणिज्यिक बैंक का हिस्सा 4880, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1316 व सहकारी बैंक 608 थे। जबकि वर्ष 2006-07 में राज्य में कुल बैंक 3550 थे। जिनमें वाणिज्यिक बैंक 2051, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 999 व सहकारी बैंक का हिस्सा 520 था, राजस्थान में कुल बैंक शाखाओं का नेटवर्क 2006-07 से 2014-15 का विवरण तालिका में दिया गया है।

राजस्थान में कुल बैंक शाखाओं का विस्तार

वर्ष	वाणिज्यिक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	कुल बैंक
2006-07	2051	999	520	3550
2007-08	2668	1022	549	4239
2008-09	2861	1040	558	4459
2009-10	3042	1052	561	4655
2010-11	3340	1068	574	4982
2011-12	3650	1105	580	5335
2012-13	3994	1157	582	5733
2013-14	4444	1236	589	6269
2014-15	4880	1316	608	6804

स्रोत: राज्य स्तर की बैंकिंग समिति (एस.एल.बी.सी.), विभिन्न मुद्दे राजस्थान

उपरोक्त तालिका 1 से स्पष्ट है कि राजस्थान में बैंकों की कुल संस्थाओं में लगातार

वृद्धि हो रही है। वर्ष 2006-07 में सभी बैंकों की शाखाओं की संख्या 3550 थी, जो कि वर्ष 2014-15 में बढ़कर दोगुनी 6804 हो गयी तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 में शाखाओं का विकास सबसे अधिक रहा।

### वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत राजस्थान के प्राथमिकता क्षेत्र में सभी बैंकों का योगदान:-

राजस्थान में प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए इनमें तेजी से वृद्धि काफी हद तक जिम्मेवार है। वार्षिक ऋण योजना के तहत, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋणा का वितरण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक से प्रत्येक वर्ष के लिए बेहतर रहा है। जो तालिका 2 में दर्शाया गया है।

### तालिका: 2 राजस्थान में वार्षिक ऋण योजना के तहत प्राथमिकता क्षेत्र में सभी संस्थाओं का योगदान (करोड़ रुपये में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
2008-09	20004	19470	97
2009-10	24507	26985	110
2010-11	29652	32229	109
2011-12	39359	39975	102
2012-13	49628	55448	112
2013-14	62790	69462	111

स्रोत: राज्य स्तर की बैंकिंग समिति (एस.एल.बी.सी.), विभिन्न मुद्दे राजस्थान

तालिका-2 से स्पष्ट है। राजस्थान के प्राथमिकता क्षेत्र में एजेन्सीवार प्रदर्शन के तहत हर वर्ष वार्षिक ऋणों में सुधार हुआ है। राजस्थान की प्राथमिकता वाले क्षेत्र में लक्ष्य सभी एजेन्सीयों द्वारा वर्ष 2008-09 में 20004 और उपलब्धि 19470 करोड़ जो कम था और वर्ष 2014-15 में ऋण लक्ष्य 78478 करोड़ रुपये व उपलब्धि 87313 करोड़ रुपये रही है यह प्रवृत्ति प्राथमिकता वाले क्षेत्र में सभी एजेन्सीयों द्वारा ऋण प्रवाह को दर्शाता है। जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुई।

वार्षिक ऋण योजना के तहत राजस्थान की प्राथमिकता क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों का प्रदर्शन (राशि करोड़ में)

ग्रामीण कारीगरों को ऋण प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वार्षिक योजना के तहत इन बैंकों के ऋण योजना प्रदर्शन में प्राथमिकता क्षेत्र में धीरे-धीरे वृद्धि हुई सारणी 3 में यह दर्शाया गया है।

**तालिका 3 राजस्थान के प्राथमिकता क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों का प्रदर्शन  
(करोड़ रुपये में)**

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
2008-09	11623	13372	115
2009-10	14712	18793	128
2010-11	17838	21125	118
2011-12	23650	25993	110
2012-13	30237	34180	113
2013-14	37770	45777	121

स्रोत: राज्य स्तर की बैंकिंग समिति (एस.एल.बी.सी.), विभिन्न मुद्दे राजस्थान

**वार्षिक योजना के तहत राजस्थान की प्राथमिकता क्षेत्र में सहकारी बैंको का योगदान**

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
2008-09	5765	3226	56
2009-10	6245	4350	70
2010-11	7476	6352	85
2011-12	9554	7871	82
2012-13	11714	14049	120
2013-14	14768	16990	115
2014-15	19482	16060	82.43

स्रोत: राज्य स्तर की बैंकिंग समिति (एस.एल.बी.सी.), विभिन्न मुद्दे राजस्थान

**वार्षिक योजना के तहत राजस्थान की प्राथमिकता क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का योगदान**

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
2008-09	2301	2688	117
2009-10	2939	3582	122
2010-11	3830	4569	119
2011-12	5599	5790	103
2012-13	7037	6937	99
2013-14	9141	6622	72
2014-15	11429	9536	83.44

स्रोत: राज्य स्तर की बैंकिंग समिति (एस.एल.बी.सी.), विभिन्न मुद्दे राजस्थान

**तालिका-7 राजस्थान में कृषि उत्पादन पर कृषि ऋण का प्रभाव**

वर्ष	उधार ऋण (लाख रु. में)	उत्पादन (मिलियन टन)
2005-06	968,769.28	18789.277
2006-07	1,226,655.28	22394.248
2007-08	1,653,681.19	23391.524
2008-09	1918,267.71	24762.488
2009-10	2170,207.39	18654.543
2010-11	2596,504.77	33675.91
2011-12	3209194.58	32153.101
2012-13	4004,635.79	30497.914
2013-14	5064,190.10	31779.348
2014-15	6070636.10	32497.442

स्रोत: राज्य स्तर की बैंकिंग समिति (एस.एल.बी.सी.), विभिन्न मुद्दे राजस्थान

**तालिका-8 कृषि उत्पादन पर कृषि ऋण के बीच सह-सम्बन्ध को प्रदर्शित करता है-**

माध्य	प्रमाप विचलन	सह-सम्बन्ध	सह-सम्बन्ध	गुणांक
उधार ऋण	2568011.79	1,323,884.13	-	-
उत्पादन	26266.48	5838.92	0.754	0.569

समीकरण-

काईवर्ग का मान  $x^2=0.019$

उपरोक्त तालिका में उत्पादन एवं बैंकों द्वारा दिये गये उत्पादन ऋणों के बीच में सह-सम्बन्ध जानने के लिए कार्ल पियर्सनके सह-सम्बन्ध गुणांक का प्रयोग किया गया है जिससे एक महत्वपूर्ण सकारात्मक पूर्ण सह-सम्बन्ध उपस्थित होने की पुष्टि होती है कृषि ऋण और उत्पादन स्तर के बीच सहसम्बन्ध गुणांक का मान = 0.569 है, जिसका यह तात्पर्य है कि यह 56.9 प्रतिशत है जो कुल कृषि ऋण प्रवाह का उत्पादन के साथ रेखीय सम्बन्ध को प्रदर्शित करता है उपरोक्त विश्लेषण से यह सिद्ध होता है कि कृषि ऋण उत्पादन बढ़ाने में कारगर साबित हुआ है अर्थात् कृषि ऋण किसानों को कृषि आदानों में सहयोग देता है अर्थात् कृषि ऋण कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

**निष्कर्ष**

किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि ऋण प्रदान किया गया है उत्पादन ऋण बीज, उर्वरक, पौधों की सुरक्षा, पशुओं से युक्त कृषि निविष्टियों के लिए निर्देशित फीड, दवाईयों, विभिन्न प्रकार का श्रम आदि। इन ऋण के लिए आसान उपलब्धता तथा ऋणों तक पहुँच में तेजी

से वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र का विकास किसानों तथा उद्योगपतियों की क्षमता में विविधता प्रदान करता है जो कृषि में नये निवेश या नई तकनीक अपनाने के रूप में दिखाई देता है। संस्थागत ऋणों ने राजस्थान में कृषि उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव दिखाया है, अनेक कारक कृषि विकास के लिए जिम्मेदार हैं जैसे अच्छे बीज, उर्वरक, मशीन कीटनाशक, पानी की उपलब्धता और श्रम शक्ति आदि इसमें कोई शक नहीं है कि बीज व अन्य सम्बन्धित प्रवृत्तियाँ मुख्य भूमिका निभाते हैं, परन्तु कृषि उत्पादन मुख्य रूप से सीधे कृषि ऋण की उपलब्धता से प्रभावित हो सकते हैं कृषि ऋण सीधे कृषि उत्पादन को प्रभावित नहीं करता है। लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। इसलिए कृषि उत्पादन में कृषि ऋण बहुत महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि ऋण की उपलब्धता नगद आदान से सम्बन्धित वित्तीय बाधाएँ, किसानों की दूसरी तकनीकी दक्षता, कृषि ऋण संसाधन आवंटन और लाभप्रदाता आदि बाधाओं को दूर करता है। इस प्रकार ऋण एक विकासशील देश में कृषि उत्पादन या उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के व्यावसायीकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है जो उत्पादन को बढ़ाता है।

#### संदर्भ

1. राज्य स्तर की बैंकिंग समिति (एस.एल.बी.सी.), राजस्थान
2. नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट 2009–2016 तक
3. राजस्थान राज्य स्टेट फोक्स पेपर 2009–2016
4. कृषि सांख्यिकीय प्रतिवेदन कृषि विभाग, राजस्थान
5. Nathuramka L.N. “Economy of Rajasthan” College Book House, Jaipur.
6. Ahuja Kanta & Rathore M.S. “Goat and Goat Keppers” Institute of Development studies (IDS), Jaipur.
7. Reserve Bank of India (RBI) “Reports of the advisory Committee on flow of credit to Agriculture”, Home report, website of RBI.